

यू. पी. राज्य

बनाम

श्रीमती सरजू देवी और अन्य

27 जुलाई, 1977

[पी. के. गोस्वामी और जसवंत सिंह, जे. जे.]

यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950- एसएस 3 (14), 212 और 212 ए.-का दायरा-प्रत्यर्थी पर वंशानुगत किरायेदारी अधिकारों के साथ तय की गई भूमि- गाँव के सभापति ने भूमि को सामान्य चरागाह भूमि होने का दावा किया- भूमि को चरागाह भूमि दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं- उप-मंडल अधिकारी ने किरायेदार को बाहर निकालने का आदेश दिया- आदेश की वैधता।

शब्द और वाक्यांश-"अभिनिर्धारित किया" का अर्थ।

उत्तर प्रदेश भूमि उपयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत, कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत दो बिचौलियों को एक नोटिस दिया, जिसमें उनसे या तो अपनी भूमि पर खेती करने या इसे अन्य व्यक्तियों को खेती के लिए पट्टे पर देने का आह्वान किया गया। इसके बाद 1950 में प्रत्यर्थी संख्या 1 पर वंशानुगत किरायेदारी अधिकारों के साथ भूमि का निपटान किया गया। 1954 में, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि विवादित भूमि सहित कुछ भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वन निपटान अधिकारी के समक्ष अपने दावे को प्राथमिकता दी। इस बीच गाँव समाज के प्रत्यर्थी सं. 5, सभापति ने

उप-मंडल अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि भूमि प्रथागत चरागाह भूमि थी और प्रत्यर्थी सं. 1, जिसने भूमि पर अतिक्रमण किया था, उसे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। उस आवेदन को मंजूर किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि उप-मंडल अधिकारी का आदेश अमान्य था और उस पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि वह भूमि पर कब्जा करने वाली सरदार थी।

निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकदमा भूमि को कभी भी राजस्व दस्तावेजों में प्रथागत चरागाह भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि खेती के लिए उपयुक्त 'परती' भूमि के रूप में दर्ज किया गया था और उप-मंडल अधिकारी के आदेश को अमान्य घोषित कर दिया। जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, यह तर्क दिया गया था कि (i) निचली अदालत ने यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि उप-मंडल अधिकारी का आदेश अमान्य था; (ii) आक्षेपित आदेश अंतिम था और (iii) कृषि से जुड़े उद्देश्य के लिए जिस भूमि पर कभी कब्जा नहीं किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 को वंशानुगत किरायेदार नहीं कहा जा सकता था।

अपील को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

(1) (ए) नीचे दिए गए न्यायालयों का यह मानना सही था कि विचाराधीन भूमि प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि नहीं थी और न ही इसका उपयोग किसी भी वर्ष में प्रथागत चरागाह भूमि या चरागाह भूमि के रूप में किया गया था। उप-मंडल अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया और आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अवैध, अप्रभावी, अमान्य था और प्रतिवादी नं. 1 पर बाध्य नहीं था। [186 बी]

(बी) 1950 के अधिनियम के एस. एस. 212-क और 212 के प्रावधानों का एक संयुक्त पठन से पता चलेगा कि धारा 121 में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष, सदस्य या सोसायटी किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कलेक्टर को केवल तभी आवेदन कर सकता है जब वह भूमि, जिसके वह कब्जे में है, धारा 212 में निर्दिष्ट विवरण की हो, अर्थात् (i) यदि इसे प्रथागत चरागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया था या (ii) यदि यह एक प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि थी। मामले में पेश किए गए साक्ष्य से यह बिल्कुल नहीं पता चलता है कि सूट भूमि को प्रथागत चरागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया था और न ही यह दर्शाता है कि यह वास्तव में प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि थी। इसके विपरीत प्रासंगिक राजस्व अभिलेखों से पता चलता है कि वे भूमि "खेती के लिए उपयुक्त" थी। [185 एच]

(2) उप-मंडल अधिकारी के आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 का अपना अधिकार स्थापित करने का मुकदमा स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य था। आक्षेपित आदेश एस के तहत पारित किया गया। 212-ए अंतिम नहीं है और यह उस पक्ष के लिए खुला है जिसके खिलाफ निष्कासन का आदेश पारित किया गया था ताकि उसके द्वारा दावा किए गए अधिकार को स्थापित करने के लिए मुकदमा दायर किया जा सके। यह केवल तभी होता है जब व्यक्ति द्वारा दायर किया गया मुकदमा विफल हो जाता है कि निष्कासन का आदेश निर्णायक हो जाता है। [186 जी]

(3) (क) इस न्यायालय ने बुधन सिंह और अन्य बनाम नबी बक्स और अन्य [1970] 2 एस. सी. आर. 10 में 1950 के अधिनियम के एस. 9 में "अभिनिर्धारित किया" शब्द की व्याख्या की, इस का अर्थ है "कानूनी अधिकार" द्वारा स्वामित्व। [187 ई]

(बी) अधिनियम में 'भूमि' शब्द की परिभाषा के अवलोकन से पता चलेगा कि भूमि का इस परिभाषा के दायरे में आना आवश्यक नहीं है, कि यह वास्तव में खेती के तहत होना चाहिए या कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए कब्जा किया जाना चाहिए। परिभाषा की आवश्यकता पूरी तरह से संतुष्ट होती है यदि भूमि या तो कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए रखी गई है या उस पर कब्जा किया गया है। परिभाषा में "अभिनिर्धारित किया" शब्द का व्यापक महत्व है। [187 ए]

तत्काल मामले में, मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से यह पाया गया है कि विचाराधीन भूमि को मई 1950 में बिचौलियों द्वारा फसल उगाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को पट्टे पर दिया गया था। यह कि वह इसके एक बड़े हिस्से को खेती के तहत लाती थी, बिचौलियों को किराया देती थी, नियमित रूप से राज्य को राजस्व का भुगतान करती थी और कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए उसने कानूनी रूप से भूमि को रखना जारी रखा था। अपीलार्थी के अपने राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भूमि को वंशानुगत किरायेदार के रूप में निहित करने की तारीख से ठीक पहले की तारीख को धारण किया था। इसलिए, उन्होंने सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया है और अधिनियम की धारा 19 के तहत निहित होने की तारीख को भूमि की सरदार बन गई हैं। [187 ई-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2334/1968

उच्च न्यायालय इलाहाबाद 1960 की दूसरी अपील संख्या 3257 के दिनांकित 5-2-1968 निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

जी. एन. दीक्षित और ओ. पी. राणा अपीलार्थी के लिए।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए फौजदार राव, जगदीश मिश्रा और यू. बी. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया

जसवंत सिंह जे. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 5 फरवरी, 1968 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें जिला न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश, बस्ती के क्रमशः 20 मई, 1960 और 27 जुलाई, 1959 के निर्णयों की पुष्टि की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1951 का यू. पी. अधिनियम संख्या 1) (जिसे इसके बाद 'यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 212 ए की उप-धारा (7) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्थापित वाद का आदेश दिया गया है, जो 26 जनवरी, 1951 को लागू हुआ था, निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न होता है: -

गाँव बौधरा, टप्पा मेंढवाल, परगना मघर पूर्व, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में स्थित विवादित भूमि की लंबाई 142 बीघा, 1 बिसवा और 18 धुर है, जो 1950 ईस्वी में गोरखपुर शहर के जमींदार गिरधर दास और पुरुषोत्तम दास की थी, जो यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम के तहत मध्यस्थ बने। यह पाते हुए कि उक्त भूमि बिना खेती के पड़ी थी, गोरखपुर के कलेक्टर ने उपरोक्त जमींदारों को यू. पी. भूमि उपयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत एक नोटिस दिया जिसमें उनसे या तो भूमि पर खेती करने या अन्य व्यक्तियों को खेती के लिए पट्टे पर देने का आह्वान किया गया था। इसके बाद उक्त जमींदारों ने मई 1950 (1357 फसली) में प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ फसल उगाने के लिए उसके पक्ष में 'पट्टा' निष्पादित करके भूमि को बसाया और उसे वंशानुगत किरायेदारी के अधिकार प्रदान किए। 1 मई, 1954 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत उत्तर प्रदेश राजपत्र में बौधारा गाँव की 342 एकड़ भूमि के संबंध में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें यह घोषणा की

गई थी कि उक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद जून, 1954 में वन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक घोषणा की गई। उत्तरदाता संख्या 1 ने वन निपटान अधिकारी के समक्ष विचाराधीन भूमि पर अपने अधिकारों के संबंध में अपने दावे को प्राथमिकता दी। 22 जनवरी, 1955 को जब प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा अभी भी लंबित था, तो प्रत्यर्थी संख्या 5 के पिता राम नरेश तिवारी ने खुद को गाँव समाज, बरईपुर के सभापति बताते हुए, यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212 ए, (1) के तहत सुह संभागीय अधिकारी, खलीलाबाद (जिसे राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दिया गया था) के समक्ष इस आधार पर एक आवेदन दायर किया कि यह एक प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि थी और इस तरह से गाँव समाज में निहित थी और उक्त प्रत्यर्थी ने उसी पर अतिक्रमण किया था। 16 अगस्त, 1955 के अपने आदेश द्वारा, उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद ने राम नरेश तिवारी के उपरोक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी संख्या 1 को बाहर निकालने का आदेश दिया। अपने निष्कासन के उपरोक्त आदेश को रद्द करने के लिए एक समीक्षा याचिका के माध्यम से असफल प्रयास करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने 15 फरवरी, 1960 को यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212-ए की उप-धारा (7) के तहत यू. पी. राज्य के खिलाफ 15 फरवरी, 1960 को उपरोक्त मुकदमा दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 के पिता राम नरेश तिवारी सहित चार अन्य लोगों ने घोषणा की कि उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश अवैध, अप्रभावी, अमान्य था और उस पर बाध्यकारी नहीं था। उसने प्रतिवादियों को उसके कब्जे और भूमि के आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी नं. 1 द्वारा स्थापित मामला यह था कि 1357 फसली (1950 ई.) में, जमींदार अर्थात् गिरधर दास और पुरुषोत्तम दास, जो विचाराधीन भूमि के कब्जे में थे, उनके पक्ष में भूमि में वंशानुगत किरायेदारी अधिकार प्रदान करते हुए पट्टों को विधिवत निष्पादित किया; कि उक्त किरायेदारी अधिकारों की पुष्टि यू. पी. किरायेदारी अधिनियम, 1939 (यू. पी. अधिनियम सं. 59 और 61) की धाराओं के तहत उनके द्वारा लाए गए मुकदमों में सक्षम राजस्व अदालतों द्वारा पारित फरमानों के आधार पर की गई थी। (1939 का यू. पी. अधिनियम XVIII) (इसके बाद 'यू. पी. टी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित); कि अधिसूचित तिथि पर 1 जुलाई, 1952 को वह यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 19 के तहत विचाराधीन भूमि की सरदार बन गई। कि 1357 फसली (1950 ईस्वी) के बाद से वह भूमि पर वास्तविक कब्जे में थी और इसका उपयोग कृषि उद्देश्यों या कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए कर रही थी और इसकी उपज का विनियोग कर रही थी और नियमित रूप से उपरोक्त जमींदारों को किराया दे रही थी और 1 जुलाई, 1952 से वह लगातार राज्य सरकार को राजस्व का भुगतान कर रही थी। कि चूंकि विचाराधीन भूमि गाँव समाज में निहित नहीं हो सकती थी और न ही गाँव समाज और न ही राम नरेश तिवारी को यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212-ए. (1) के तहत आवेदन करने का कोई अधिकार था और यह कि भूमि 8 अगस्त, 1946 से पहले या उसके बाद एक सामान्य चरागाह भूमि या एक प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि नहीं थी, लेकिन उपरोक्त पट्टाओं के निष्पादन तक उपरोक्त जमींदारों के अनन्य कब्जे और स्वामित्व में होने के कारण और उनके अनन्य कब्जे में उनके निष्पादन के बाद, यह उस प्रकृति की भूमि नहीं थी जिसे वैध रूप से यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212 के दायरे में आने के लिए कहा जा सकता था और उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा यू. पी. जेड. ए. और

एल. आर. अधिनियम की धारा 212-ए के तहत की गई कार्यवाही अवैध, शून्य और अमान्य थी।

इसमें अकेले अपीलार्थी ने मुकदमे का विरोध किया। बाकी प्रतिवादियों ने समन की सेवा के बावजूद अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना, उनके खिलाफ मामला एकतरफा आगे बढ़ा। अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ अनुरोध किया कि चूंकि यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम के प्रवर्तन से पहले या बाद में भूमि कभी भी उपरोक्त जमींदारों के वास्तविक कब्जे में नहीं थी, इसलिए यह राज्य सरकार में निहित थी। कि भूमि हमेशा सार्वजनिक उपयोगिता की एक प्रथागत चरागाह भूमि बनी हुई थी जिसमें जमींदारों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई किरायेदारी या अन्य अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता था; कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्भर पट्टे का लेन-देन अमान्य और अप्रवर्तनीय था; कि मुकदमा कानूनी रूप से गाँव समाज में निहित है और उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा पारित 16 अगस्त, 1955 का आक्षेपित निष्कासन आदेश प्रतिवादी संख्या 1 पर बाध्यकारी था और उसके द्वारा लाया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मुकदमा भूमि को कभी भी राजस्व पत्र में प्रथागत चरागाह भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, बल्कि 1357 फसली (1950 ईस्वी) से संबंधित खातोनी में "खेती के लिए उपयुक्त परती भूमि" के रूप में दर्ज किया गया था। कि अपीलार्थी के इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वाद भूमि का उपयोग किसी भी वर्ष में सामान्य चरागाह भूमि या चरागाह भूमि के रूप में किया गया था; कि अपीलार्थी को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वाद भूमि का लगभग 10 या 12 बीघा भाग प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा खेती के अंतर्गत लाया गया था; कि वाद भूमि मई 1950

में प्रत्यर्थी संख्या 1 को पट्टे पर दी गई थी जब वह उसी की वंशानुगत किरायेदार बन गई थी; यह कि वाद भूमि एक प्रथागत चरागाह भूमि नहीं है, उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा पारित 16 अगस्त, 1955 का आदेश अवैध, अमान्य और वादी के लिए बाध्यकारी नहीं था। निचली अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि उसे राजस्व पत्रों में भूमि के वंशानुगत किरायेदार के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को सक्षम राजस्व अदालतों द्वारा 1950 के 1178, 1950 के 780 और 1952 के 285 के मुकदमों में भी वंशानुगत किरायेदार के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था और यह कि वह निहित होने की तारीख को वाद भूमि की सरदार बन गई थी। इन निष्कर्षों के साथ, सिविल न्यायाधीश, बस्ती ने 27 जुलाई, 1959 के अपने निर्णय और डिक्री द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खर्च के साथ मुकदमे का फैसला सुनाया। इस निर्णय और डिक्री से व्यथित, यू. पी. राज्य ने जिला न्यायाधीश, बस्ती को अपील की, जिन्होंने 20 मई, 1960 के अपने फैसले और डिक्री द्वारा निचली अदालत के उपरोक्त फैसले और डिक्री की पुष्टि की, जिसमें कहा गया था कि वाद भूमि को फसल उगाने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 को पट्टे पर दिया गया था। कि वर्ष 1358, 1359 और 1362 फसली से संबंधित राजस्व पत्रों (प्रदर्शनी 1, 7 और 8) में, उन्हें सूट भूमि के वंशानुगत किरायेदार के रूप में दर्ज किया गया था और वह निहित होने की तारीख 1 जुलाई, 1952 को उसकी सरदार बन गई थी। आगे की अपील पर, उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी, 1968 के अपने फैसले द्वारा निचली अदालत और जिला न्यायाधीश, बस्ती के उपरोक्त फैसलों और फरमानों को बरकरार रखा। यह इस निर्णय और डिक्री के खिलाफ है कि यू. पी. राज्य इस न्यायालय में अपील करने आया था।

अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए, श्री दीक्षित ने आग्रह किया है कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री अदालतों के निष्कर्षों की गारंटी नहीं देती है कि मुकदमा यू. पी.

जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212 द्वारा अनुध्यात प्रकृति का नहीं है, उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश अमान्य था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश अंतिम और निर्णायक था और जिस वाद से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है वह बनाए रखने योग्य नहीं था। उन्होंने अंत में प्रस्तुत किया है कि यह यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 3 (14) में निहित "भूमि" की परिभाषा है न कि यू. पी. टी. अधिनियम की धारा 3 (1) में निहित परिभाषा जो तत्काल मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है और यह कि जिस भूमि पर कभी भी कृषि से जुड़े उद्देश्य के लिए कब्जा नहीं किया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 को उसका वंशानुगत किरायेदार नहीं कहा जा सकता है और नीचे की अदालतों ने उसे उसका सरदार घोषित करने में गलती की है। हम इन बिंदुओं पर क्रमिक रूप से विचार करेंगे।

प्वाइंट नंबर 1: इस बिंदु के उचित निर्धारण के लिए, यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212-ए. (1) का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसके तहत शिव राम तिवारी के पिता, प्रतिवादी संख्या 5, राम नरेश तिवारी द्वारा उपरोक्त आवेदन किया जाना अपेक्षित है और उसी अधिनियम की धारा 212 का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसका उल्लेख धारा 212-ए. (1) में किया गया है:

"212-ए (1). धारा 212 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 121 में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष, सदस्य या सोसायटी, धारा 212 में निर्दिष्ट भूमि के कब्जे वाले व्यक्ति की भूमि से बेदखल करने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है।

(7) जहां इस धारा के तहत निष्कासन का आदेश पारित किया गया है, वह पक्ष जिसके खिलाफ आदेश पारित किया गया है, उसके द्वारा दावा किए गए अधिकार को स्थापित करने के लिए एक मुकदमा दायर कर सकता है, लेकिन ऐसे मुकदमे के

परिणामों के अधीन रहते हुए उप-धारा (4) या (6) के तहत पारित आदेश निर्णायक होगा।

"212. सार्वजनिक उपयोग की भूमि से व्यक्तियों को निकालना। कोई भी व्यक्ति, जिसे अगस्त 1946 के आठवें दिन या उसके बाद कार्यकाल या उपवन धारक के रूप में भर्ती किया गया है, या एक मध्यस्थ होने के नाते, अपनी खेती के तहत लाया है या उस भूमि पर एक उपवन लगाया है, जिसे प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि, दाह संस्कार या कब्रिस्तान, तालाब पथ या खालियन के रूप में दर्ज किया गया था, गाँव सभा के मुकदमे पर धारा 199 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि से बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसे मुआवजे के भुगतान पर जो निर्धारित किया जाए।"

इन दोनों धाराओं के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि धारा 121 में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष, सदस्य या सोसायटी किसी व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए कलेक्टर को केवल तभी आवेदन कर सकती है जब वह भूमि, जिस पर उसका कब्जा है, धारा 212 में निर्दिष्ट विवरण की हो, यानी (1) यदि इसे प्रथागत चरागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया था या (2) यदि यह एक प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि थी। मामले में पेश किए गए साक्ष्य से यह बिल्कुल नहीं पता चलता है कि सूट भूमि को प्रथागत चरागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया था और न ही यह दर्शाता है कि यह वास्तव में प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि थी।

इसके विपरीत, अपीलार्थी का अपना अभिलेख स्पष्ट रूप से उसके मामले को नकारता है। प्रदर्शनी 2 और 45 में, जो 1323 फसली की बस्ती खातोनी की प्रतियां हैं, विचाराधीन भूमि को स्पष्ट रूप से लंबी घास के साथ 'परती' के रूप में दर्ज किया गया है। फिर से 1357 फसली (1950 ई.) के खातोनी में, भूमि को 'खेती के लिए उपयुक्त' के रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए, नीचे दी गई अदालतें यह अभिनिर्धारित करने में

पूरी तरह से सही थीं कि अपीलार्थी के इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि विचाराधीन भूमि को या तो प्रथागत सामान्य चरागाह भूमि के रूप में दर्ज किया गया था या किसी भी वर्ष में पारंपरिक चरागाह भूमि या चरागाह भूमि के रूप में उपयोग किया गया था। इसलिए स्पष्ट रूप से, उप-मंडल ओटिसेर, खलीलाबाद ने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया और प्रत्यर्थी संख्या 1 को बाहर निकालने का निर्देश देने वाला उनके द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अवैध, अप्रभावी, अमान्य और प्रत्यर्थी संख्या 1 पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं था।

बिंदु संख्या 2: - श्री दीक्षित द्वारा आग्रह किया गया दूसरा बिंदु भी सारहीन है। यहां तक कि यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 212-ए की उप-धारा (7) पर एक सरसरी नज़र डालने से यह पता चलता है कि उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा धारा 212-ए के तहत पारित आदेश अंतिम नहीं हैं और यह उस पक्ष के लिए खुला है जिसके खिलाफ निष्कासन का आदेश पारित किया जाता है ताकि वह अपने द्वारा दावा किए गए अधिकार को स्थापित करने के लिए एक मुकदमा दायर कर सके। यह केवल तभी होता है जब व्यक्ति द्वारा दायर किया गया मुकदमा विफल हो जाता है कि निष्कासन का आदेश निर्णायक हो जाता है। इसलिए, उप-मंडल अधिकारी, खलीलाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए लाया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य था।

प्वाइंट नंबर 3: - इस बिंदु के निर्णय के लिए, यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 3 (14) और 19 का उल्लेख करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है: -

"3(14). भूमि (धारा 109,143 और 144 और अध्याय 7 को छोड़कर) का अर्थ है कृषि, बागवानी या पशुपालन से जुड़े उद्देश्यों के लिए धारित या कब्जा की गई भूमि जिसमें मत्स्य पालन और मुर्गी पालन शामिल है।

19. किसी भी व्यक्ति द्वारा निहित करने की तारीख से तुरंत पहले के आंकड़ों पर धारित या मानी गई सभी भूमि इस प्रकार है:

(i)

(ii)

(iii)

(iv) एक वंशानुगत किरायेदार

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में उपबंधित मामलों में राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता किया गया समझा जाएगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 18 की उप-धारा (2) में उपबंधित के अलावा, उसके सरदार के रूप में कब्जा लेने या बनाए रखने का हकदार होगा।

यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 3 (14) में निहित "भूमि" शब्द की परिभाषा का केवल अवलोकन, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि भूमि का इस परिभाषा के दायरे में आना आवश्यक नहीं है कि वह वास्तव में खेती के अधीन हो या कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए उस पर कब्जा किया गया हो। परिभाषा की आवश्यकता, हमारी राय में, पूरी तरह से संतुष्ट है यदि भूमि या तो कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए आयोजित या कब्जा कर ली गई है। उपरोक्त परिभाषा में आने वाला "अभिनिर्धारित" शब्द, जो "धारण" शब्द का एक पी. पी. पी. एल. है, व्यापक महत्व का है। "द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज" के असंकलित संस्करण में, "होल्ड" शब्द का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ "स्वामित्व या उपयोग होना" बताया गया है। अपने के रूप में रखें "। अर्ल जोविट (1959 संस्करण) द्वारा 'द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लॉ' में, "होल्ड" शब्द की व्याख्या "किरायेदार के रूप में होना" के रूप में की गई है।

स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश (चौथा संस्करण) में, स्वामित्व और व्यवसाय के बीच के अंतर को आर. बनाम डिटचेट में लिटलडेल, जे. द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करके सामने लाने की कोशिश की गई है।

"स्वामित्व और व्यवसाय के बीच एक भौतिक अंतर है। एक व्यक्ति रख सकता है, हालांकि वह कब्जा नहीं करता है। एक किरायेदार वह व्यक्ति है जो दूसरे को धारण करता है; वह आवश्यक रूप से कब्जा नहीं करता है।

वेबस्टर के न्यू ट्वेंटीएथ सेंचुरी डिक्शनरी (दूसरा संस्करण) में, यह कहा गया है कि कानूनी भाषा में, "अभिनिर्धारित" शब्द का अर्थ है "कानूनी शीर्षक" द्वारा धारण करना। इस अर्थ पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय बुधन सिंह और अन्य बनाम नबी

बक्स और अन्य में यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 9 में "आयोजित" शब्द की व्याख्या की जिसका अर्थ है कानूनी अधिकार द्वारा कब्जा।

तत्काल मामले में, मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नीचे की अदालतों द्वारा समवर्ती रूप से यह पाया गया है कि विचाराधीन भूमि को मई, 1950 (1357 फसली) में फसलों को उगाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया था। कि उन्होंने इसके एक बड़े हिस्से को खेती के तहत लाया, उचित प्राप्ति के बदले 1951 और 1952 में गिरधर दास और पुरुषोत्तम दास को किराया दिया; कि वह नियमित रूप से अपीलार्थी को राजस्व का भुगतान कर रही है और उसने कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से भूमि पर कब्जा करना जारी रखा है। अपीलार्थी के अपने राजस्व रिकॉर्ड से यह भी स्थापित होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भूमि को वंशानुगत किरायेदार के रूप में निहित करने की तारीख से ठीक पहले की तारीख को धारण किया था। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया और यू. पी. जेड. ए. और एल. आर. अधिनियम की धारा 19 के तहत निहित होने की तारीख को भूमि की सरदार बन गई।

इसलिए, अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाए गए सभी तर्क विफल हो जाते हैं।

पूर्वगामी कारणों से, हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं जिसे खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थी 12 नवंबर, 1968 के न्यायालय के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 की लागत का भुगतान करेगा।

पी.बी.आर.

अपील खारिज की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक कैलाश पूनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।